

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 10-11-2025

विषय सूची

- » भारत की आयनी एयरबेस से वापसी
- » कार्यात्मक खाद्य पदार्थ (Functional Foods)
- » नोटबंदी के नौ वर्ष पश्चात्“
- » आदित्य-एल1 मिशन द्वारा कोरोनाल मास इजेक्शन (CMEs) की निगरानी
- » जलवायु परिवर्तन और उर्वरक असंतुलन से मृदा स्वास्थ्य प्रभावित: ICAR अध्ययन
- » EEZ में मत्स्य पालन के सतत दोहन के नियम
- » कृषि में डीप-टेक क्रांति को आकार देने वाली रिपोर्ट: WEF

संक्षिप्त समाचार

- » चित्तरंजन दास
- » वैश्विक शांति प्रार्थना महोस्तव
- » अंगोला
- » असम बहुविवाह निषेध विधेयक-2025
- » भारत विकास और रणनीतिक कोष (IDSF)
- » बॉक्सफिश

भारत की आयनी एयरबेस से वापसी समाचार में

- भारत ने ताजिकिस्तान में स्थित आयनी एयरबेस पर अपने संचालन को बंद कर दिया है। यह एक प्रमुख विदेशी सुविधा थी, जिसने मध्य एशिया में भारत को रणनीतिक प्रभाव प्रदान किया था।

आयनी एयरबेस

- यह एयरबेस मूल रूप से सोवियत युग के दौरान बनाया गया था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यह खराब स्थिति में था।



- भारत ने 2002 से लगभग 80 मिलियन डॉलर का निवेश करके इसे उन्नत किया, जिसमें 3,200 मीटर लंबा रनवे, हेंगर, ईंधन डिपो और एयर ट्रैफिक कंट्रोल शामिल थे।
- इसका अधिकांश कार्य सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा किया गया।
- यह ताजिकिस्तान में स्थित है और अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से लगभग 20 किमी दूर है, जो पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) एवं चीन के शिनजियांग प्रांत से सीमा साझा करता है।

महत्व

- आयनी भारत का एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी बेस था, और इसका स्थान भारत को मध्य एशिया में सैन्य उपस्थिति और पाकिस्तान पर दबाव बनाने का अवसर देता था।

- इसने 2021 में तालिबान की वापसी के बाद निकासी अभियानों को भी सुगम बनाया।
- यह एक रणनीतिक भारतीय सैन्य चौकी के रूप में कार्य करता था और प्रारंभ में तालिबान के विरुद्ध उत्तरी गठबंधन को भारत के समर्थन के दौरान उपयोग किया गया था।
- अपने चरम पर, यहां लगभग 200 भारतीय कर्मी और सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान तैनात थे।
- इसकी उपस्थिति ने रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में भारत के प्रभाव को प्रदर्शित किया।

हालिया वापसी के पीछे कारण

- भारत ने 2022 में ताजिकिस्तान के आयनी एयरबेस से वापसी कर ली, जब इस सुविधा के पुनर्वास और विकास के लिए द्विपक्षीय समझौता समाप्त हो गया।
- रिपोर्टों के अनुसार, ताजिक सरकार ने रूस और चीन के दबाव के कारण लीज़ को नवीनीकृत करने से मना कर दिया।
- यह गोपनीय तरीके से की गई और हाल ही में सामने आई।
- इसकी हानि भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के लिए एक आघात माना जा रहा है, विशेषकर विगत दो दशकों में किए गए बड़े निवेश को देखते हुए।

क्या आप जानते हैं?

- भारत वर्तमान में कोई भी कार्यशील विदेशी सैन्य बेस संचालित नहीं करता।
- हालांकि, 2024 में इसने मॉरीशस के अगालेगा द्वीपों पर एक रणनीतिक हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया, जिससे पश्चिमी हिंद महासागर में इसकी समुद्री पहुंच एवं अफ्रीका के पूर्वी तट पर निगरानी क्षमता बढ़ी।
- भारत भूटान में रॉयल भूटान आर्मी और बॉडीगार्ड के लिए एक सैन्य प्रशिक्षण दल भी बनाए रखता है।
- भारत ने 1971 के युद्ध और IPKF मिशन के दौरान अस्थायी रूप से बांग्लादेश एवं श्रीलंका से भी संचालन किया था।

- इसके विपरीत, चीन का जिबूती में एक आधिकारिक बेस है और वह ताजिकिस्तान में एक और बेस बना रहा है, जबकि अमेरिका के पास विश्वभर में 100 से अधिक विदेशी बेस हैं, जिनमें दक्षिण कोरिया, क्रतर, जर्मनी और जापान में प्रमुख ठिकाने शामिल हैं।

Source :IE

कार्यात्मक खाद्य पदार्थ (Functional Foods)

समाचार में

- समाज का भोजन के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो रहा है, तथा आगामी बड़ा परिवर्तन कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और स्मार्ट प्रोटीन पर केंद्रित है, जो बेहतर स्वास्थ्य एवं स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।

कार्यात्मक खाद्य पदार्थ (Functional Foods)

- ये ऐसे समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं या रोगों को रोकते हैं, जैसे विटामिन-संवर्धित चावल या ओमेगा-3 युक्त दूध।
- ये कई तकनीकों का उपयोग करते हैं जैसे न्यूट्रिजेनोमिक्स (पोषण और जीन के बीच संबंधों का अध्ययन), जैव-संवर्धन, 3D फूड प्रिंटिंग और बायोप्रोसेसिंग।

स्मार्ट प्रोटीन (Smart Proteins)

- इसका अर्थ है जैव-प्रौद्योगिकी से प्राप्त प्रोटीन, जिनका उद्देश्य पारंपरिक उत्पादन पर निर्भरता को कम करना है।
- इसमें पौधों से प्राप्त प्रोटीन (दलहन, अनाज या तिलहन से पुनर्गठित अर्क जो पशु मांस और डेयरी की नकल करते हैं); किण्वन-आधारित प्रोटीन (सूक्ष्मजीव प्रणालियों द्वारा उत्पादित); और संवर्धित मांस (बायोरिएक्टर में बिना वध किए पशु कोशिकाओं को उगाकर तैयार किया गया) शामिल हैं।

भारत में आवश्यकता

- भारत एक अत्यंत असमान पोषण परिदृश्य का सामना कर रहा है, जहां एक-तिहाई से अधिक बच्चे अविकसित हैं और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोटीन सेवन में लगातार असमानताएँ हैं।

- जैसे-जैसे आय बढ़ती है, ध्यान खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर स्थानांतरित होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार पर बल दिया जाए।
- इसे प्राप्त करने के लिए पोषण लक्ष्यों को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करना आवश्यक है, ताकि एक लचीला और जलवायु-सचेत खाद्य प्रणाली बनाई जा सके।
- कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन जैसी नवाचार तकनीकें व्यावहारिक समाधान प्रदान करती हैं, जो दैनिक आहार के पोषण मूल्य को बढ़ाती हैं बिना पारिस्थितिक दबाव को बढ़ाए।

भारत में स्थिति

- भारत अपनी BioE3 नीति के अंतर्गत कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और स्मार्ट प्रोटीन में स्थिर प्रगति कर रहा है, जिसे जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) एवं BIRAC का समर्थन प्राप्त है।
- मुख्य विकासों में जैव-संवर्धित फसलें जैसे जिंक-समृद्ध चावल (IIRR, हैदराबाद) और आयरन-समृद्ध बाजरा (ICRISAT) शामिल हैं, साथ ही टाटा, ITC एवं मैरिको जैसी निजी कंपनियों द्वारा संवर्धित खाद्य पदार्थों में निवेश।
- स्मार्ट प्रोटीन क्षेत्र तीव्रता से विस्तार कर रहा है, जहाँ 2023 तक 70 से अधिक ब्रांड 377 पौध-आधारित मांस, अंडा और डेयरी उत्पाद प्रस्तुत कर रहे हैं।
- गुडडॉट और इवो फूड्स जैसी स्टार्टअप कंपनियाँ नवाचार का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि ज़ाइडस लाइफसाइंसेज ने 2024 में किण्वन-आधारित प्रोटीन में प्रवेश किया।
- DBT ने सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में संवर्धित मांस अनुसंधान को भी वित्त पोषित किया है।
- हालाँकि, FSSAI से नियामक स्पष्टता और बड़े पैमाने पर किण्वन तथा गुणवत्ता परीक्षण के लिए बुनियादी ढाँचे की कमी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

वैश्विक परिवर्तन

- जापान ने 1980 के दशक में कार्यात्मक खाद्य पदार्थों की अवधारणा और नियमन की शुरुआत की।
- स्मार्ट प्रोटीन एक नई नवाचार है, जिसमें सिंगापुर 2020 में व्यावसायिक बिक्री के लिए संवर्धित चिकन को स्वीकृति देने वाला प्रथम देश बना।
- चीन ने वैकल्पिक प्रोटीन को अपनी खाद्य सुरक्षा और नवाचार एजेंडा में शामिल किया है, जबकि यूरोपीय संघ अपनी “फार्म तो फोर्क(farm to Fork)” रणनीति के माध्यम से स्थायी प्रोटीन उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है।

आगे की राह

- पोषण सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भारत को कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और स्मार्ट प्रोटीन की क्षमता का उपयोग करना चाहिए, जो महत्वपूर्ण आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान कर सकते हैं।
- वैश्विक पौध-आधारित खाद्य बाजार 2030 तक 240 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है, जिससे भारत एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर सकता है और कृषि, विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स में रोजगार उत्पन्न कर सकता है।
- पर्यावरणीय दृष्टि से, जैव-आधारित प्रोटीन उत्सर्जन और संसाधन दबाव को कम करने का मार्ग प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

- हालांकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं जिनमें नियामक खामियाँ, गलत लेबल वाले उत्पादों का जोखिम, सीमित बुनियादी ढाँचा और प्रयोगशाला में उगाए गए खाद्य पदार्थों के प्रति सार्वजनिक संदेह शामिल हैं।
- इनसे निपटने के लिए भारत को FSSAI के अंतर्गत एक स्पष्ट राष्ट्रीय नियामक ढाँचे, समन्वित नीतिगत समर्थन और बेहतर सार्वजनिक-निजी साझेदारी की आवश्यकता है, ताकि जैव-निर्माण को बढ़ाया जा सके और प्रिसीजन फर्मेंटेशन जैसी तकनीकों का स्थानीयकरण किया जा सके।

- जन-जागरूकता और किसानों को नई मूल्य शृंखलाओं में शामिल करना समान एवं स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

Source :TH

“नोटबंदी के नौ वर्ष पश्चात्”

संदर्भ

- 2016 में सरकार द्वारा नोटबंदी की घोषणा के बाद से जनता के पास मौजूद मुद्रा दोगुने से भी अधिक हो गई है।

नोटबंदी (Demonetisation)

- प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की। इसमें कहा गया कि सभी मौजूदा ₹500 और ₹1,000 के नोट, जो प्रचलन में कुल मुद्रा का लगभग 86% थे, अब वैध मुद्रा नहीं रहेंगे।
- 2016 की नोटबंदी का उद्देश्य काले धन को समाप्त करना, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना था।

जनता के पास मुद्रा (Currency with Public)

- जनता के पास मुद्रा की गणना कुल प्रचलन में मुद्रा (CIC) से बैंकों के पास नकदी घटाकर की जाती है।
 - CIC का अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट और सिक्के, जिनका उपयोग उपभोक्ताओं एवं व्यवसायों के बीच लेन-देन के लिए भौतिक रूप से किया जाता है।
- नोटबंदी के नौ वर्ष बाद भी जनता के पास मुद्रा का स्तर ऊँचा है, हालांकि सरकार और RBI ने कम-नकदी समाज की दिशा में प्रयास किए हैं।
- हालांकि, अर्थव्यवस्था का आकार भी प्रत्येक वर्ष 6% से अधिक की वृद्धि के साथ बढ़ा, जिससे प्रचलन में मुद्रा का GDP अनुपात नोटबंदी से पहले के स्तर से नीचे आ गया।

क्या मुद्रा में वृद्धि वास्तविक तस्वीर दिखाती है?

- प्रचलन में मुद्रा की संख्या में वृद्धि वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि GDP वृद्धि बेहतर रही है और FY2026 की प्रथम तिमाही में 7.8% तक पहुँची।

- 2016 की नोटबंदी के बाद से, प्रचलन में मुद्रा प्रत्येक वर्ष लगातार बढ़ी है, और CIC से GDP का अनुपात 2016-17 में 8.7% से बढ़कर 2020-21 में 14.5% हो गया।
 - ▲ अब यह अनुपात 2025 में घटकर 11.11% हो गया है, जबकि मार्च 2016 में यह 12.1% था।
- उच्च CIC-GDP अनुपात दर्शाता है कि लोग और व्यवसाय लेन-देन के लिए नकदी पर अधिक निर्भर हैं, जबकि कम अनुपात डिजिटल भुगतान, बैंकिंग चैनलों एवं औपचारिक वित्तीय प्रणालियों की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- कम CIC-GDP अनुपात, जो बढ़ती डिजिटलीकरण और नकदी पर कम निर्भरता से प्रेरित है, सामान्यतः मौद्रिक नीति के सुचारू प्रसारण एवं बेहतर मुद्रास्फीति नियंत्रण को सक्षम बनाता है।

भारत का CIC-GDP अनुपात अन्य देशों की तुलना में

- नोटबंदी और कोविड काल के बाद, यद्यपि भारत का मुद्रा-से-GDP अनुपात सुधरा है, यह अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है।
- जापान का अनुपात 9-11%, यूरोज़ोन का 8-10% और चीन का 9.5% है।
 - ▲ रूस का अनुपात 8.3% और अमेरिका का 7.96% है।

- भारत का उच्च 11.11% अनुपात इसके बड़े नकदी-निर्भर अनौपचारिक क्षेत्र, नकदी रखने की सांस्कृतिक प्राथमिकता, सीमित कार्ड उपयोग और तुलनात्मक रूप से कम अपनाने से उत्पन्न होता है।
- साथ ही, भारत तेज़ी से डिजिटल भुगतान प्रणालियों को भी अपना रहा है, जबकि अमेरिका, यूरोज़ोन, चीन और रूस जैसी अर्थव्यवस्थाएँ पहले से ही अत्यधिक औपचारिक एवं डिजिटल हैं।

भारत की मुद्रा आपूर्ति की गतिशीलता: नोटबंदी से डिजिटलीकरण तक

- **नोटबंदी (2016)** ने अल्पकालिक मांग आधार उत्पन्न किया: MSME पर दबाव, रोजगारों की हानि और तरलता की कमी। GDP वृद्धि अस्थायी रूप से 6% से नीचे चली गई।
- **डिजिटलीकरण में वृद्धि:** 2016 के बाद, UPI लेन-देन 2025 तक ₹20 लाख करोड़/माह से अधिक हो गए, जो टियर-2/3 शहरों तक गहराई से फैले और खुदरा भुगतान में नकदी के स्थान पर उपयोग का संकेत दिया।
- **मुद्रा-से-GDP अनुपात:** 2016 में 12% से घटकर 2024 में लगभग 10.5% हो गया, जो नकदी की कम तीव्रता को दर्शाता है, हालांकि बड़े अनौपचारिक क्षेत्र के कारण यह अभी भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है।

RBI की मुद्रा आपूर्ति की माप (Measures of Money Supply)

- अप्रैल 1977 में पेश की गई, RBI मुद्रा आपूर्ति को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है — M1, M2, M3 और M4 — जिन्हें तरलता के घटते क्रम में रखा गया है।
 - ▲ **M1 (संकीर्ण मुद्रा):** जनता के पास मुद्रा + बैंकों में माँग जमा (अंतर-बैंक को छोड़कर) + RBI में अन्य जमा।
 - ▲ **M2:** M1 + डाकघर बचत बैंक जमा।
 - ▲ **M3 (व्यापक मुद्रा):** M1 + वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों में समय जमा।
 - ▲ **M4:** M3 + सभी डाकघर जमा (समय और माँग दोनों)।

Money Type	Includes	Narrow/Broad	Rank (Liquidity)
M1	Currency with public (coins, currency notes), Net demand deposits held by the public with commercial banks & other deposits with RBI	Narrow Money	1 (Most Liquid)
M2	M1 + savings deposits with post office	Narrow Money	2
M3	M1 + time deposits with the banking system (such as fixed deposits)	Broad Money	3
M4	M3 + all deposits with post office savings organizations, excluding National Savings Certificates	Broad Money	4 (Least Liquid)

- नीतिगत उपयोग: इनमें से, M3 RBI द्वारा मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण और व्यापक आर्थिक आकलन के लिए मुख्य माप है, जैसा कि चक्रवर्ती समिति (1982–85) ने अनुशासित किया था।

M3 क्यों महत्वपूर्ण है?

- यह मुद्रा और जमा दोनों को समाहित करता है, जो व्यय, बचत और क्रण सृजन को प्रभावित करते हैं।
- यह मध्यम अवधि की नीतिगत विश्लेषण के लिए संकरी मापों की तुलना में अधिक स्थिर और विश्वसनीय है।
- यह तरलता की स्थिति को दर्शाता है, जो बैंक बैलेंस शीट और क्रण प्रसारण को प्रभावित करती है।

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital Economy in India)

- नोटबंदी के बाद, डिजिटल अर्थव्यवस्था तीव्रता से बढ़ रही है, जिसने 2022–23 में राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया और 2024–25 तक 13.42% तक पहुँचने की संभावना है।
- ICRIER द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया स डिजिटल इकॉनमी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत अब अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- 2030 तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग पाँचवाँ हिस्सा बनने का अनुमान है, जो पारंपरिक क्षेत्रों की वृद्धि को पीछे छोड़ देगी।

Key Milestones of the Digital India Journey



Source: IE

आदित्य-एल1 मिशन द्वारा कोरोनाल मास इजेक्शन (CMEs) की निगरानी

समाचार में

- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान और नासा के वैज्ञानिकों ने प्रथम बार सूर्य की सतह के निकट दृश्य तंरंगदैर्घ्य सीमा में कोरोनल मास इजेक्शन (CME) का स्पेक्ट्रोस्कोपिक

अवलोकन किया है। यह अवलोकन आदित्य-एल1 पर लगे VELC पेलोड का उपयोग करके किया गया।

आदित्य-एल1 (Aditya-L1)

- यह भारत का प्रथम अंतरिक्ष-आधारित सौर वेधशाला है, जिसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए लैग्रेंज बिंदु 1 से डिज्जाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है।
 - यह स्थिति सूर्य संबंधी घटनाओं का अविराम अवलोकन करने की अनुमति देती है, जिसमें ग्रहण या अन्य अवरोध नहीं होते।
- सितंबर 2023 में इसका प्रक्षेपण किया गया ताकि सौर गतिशीलता को बेहतर तरीके से समझा जा सके, जिसमें कोरोनल मास इजेक्शन (CME), सौर ज्वालाएँ और उनका अंतरिक्ष मौसम पर प्रभाव शामिल है — जो पृथ्वी पर उपग्रह संचालन, संचार एवं विद्युत ग्रिड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- इस मिशन में सात स्वदेशी रूप से विकसित पेलोड हैं, जिनमें पाँच इसरो द्वारा और दो भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से बनाए गए हैं।
- ये उपकरण सूर्य के प्रकाशमंडल (Photosphere), वर्णमंडल (Chromosphere) और कोरोना का अवलोकन करने, सौर उत्सर्जन एवं चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन तथा सौर पवन और ऊर्जावान कण प्रवाह का अध्ययन करने के लिए बनाए गए हैं।

लैग्रेंज बिंदु (Lagrange Points)

- लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वे स्थान हैं जहाँ दो विशाल पिंडों (जैसे सूर्य और पृथ्वी) का गुरुत्वाकर्षण बल और किसी छोटे पिंड (जैसे अंतरिक्ष यान) पर लगने वाला अभिकेन्द्रीय बल एक-दूसरे को संतुलित करते हैं।

- इससे छोटा पिंड दोनों बड़े पिंडों के सापेक्ष अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है।
- सूर्य-पृथ्वी प्रणाली में ऐसे पाँच बिंदु (L1-L5) होते हैं।

हेलो कक्षा (Halo Orbit)

- लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक त्रि-आयामी आवधिक कक्षा है जो साधारण वृत्ताकार कक्षा के विपरीत, यह L1 के चारों ओर एक लूप जैसी (हेलो) पथ बनाती है।
- यह अंतरिक्ष यान को पृथ्वी या चंद्रमा की सीधी छाया से बचने में सहायता करती है और न्यूनतम ईंधन खपत के साथ स्थिर स्थिति बनाए रखती है।

रणनीतिक महत्व (Strategic Significance)

- आदित्य-एल1 निरंतर सौर निगरानी प्रदान करेगा, जिससे अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं और उनके पृथ्वी पर प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी।
- यह वैश्विक सौर अनुसंधान को समर्थन देगा और नासा के पार्कर सोलर प्रोब तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के सोलर ऑर्बिटर जैसे मिशनों का पूरक होगा।
- यह वेधशाला-स्तरीय अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- यह भारत की व्यापक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है, जिनमें आगामी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन और अंतरग्रहीय अन्वेषण शामिल हैं।

Sources: TH

जलवायु परिवर्तन और उर्वरक असंतुलन से मृदा स्वास्थ्य प्रभावित: ICAR अध्ययन संदर्भ

- हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने चिंताजनक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि अवैज्ञानिक उर्वरक उपयोग और जलवायु परिवर्तन भारत की कृषि योग्य मृदा में कार्बनिक कार्बन के गंभीर क्षरण का कारण बन रहे हैं।

मुख्य निष्कर्ष

- असंतुलित उर्वरक उपयोग:** अध्ययन में पाया गया कि असंतुलित और अत्यधिक उर्वरक उपयोग —

विशेषकर यूरिया एवं फॉस्फोरस — ने मृदा के कार्बन स्तर को क्षतिग्रस्त किया है।

- हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहन एवं अवैज्ञानिक उर्वरक उपयोग के कारण सबसे गंभीर गिरावट देखी गई।
- बिहार, जहाँ उर्वरकों का अधिक संतुलित उपयोग किया गया, ने बेहतर मृदा कार्बन स्वास्थ्य प्रदर्शित किया।
- कार्बनिक कार्बन और ऊँचाई का संबंध:** पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा में अधिक कार्बनिक कार्बन पाया गया, जबकि मैदानी क्षेत्रों की मृदा में कमी देखी गई।
- कम मृदा कार्बन से ऊष्मा परावर्तन बढ़ता है, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव और वैश्विक ऊष्मीकरण का जोखिम बढ़ता है।
- तापमान का नकारात्मक प्रभाव:** अध्ययन चेतावनी देता है कि बढ़ते तापमान मृदा के कार्बनिक कार्बन को और कम कर सकते हैं, जिससे मृदा का स्वास्थ्य और जलवायु प्रभाव खराब हो सकते हैं।
- राजस्थान और तेलंगाना जैसे गर्म क्षेत्रों में कार्बनिक पदार्थ के तीव्र विघटन के कारण मृदा में कार्बनिक कार्बन (SOC) की मात्रा कम पाई गई।
- वर्षा और फसल प्रणाली का प्रभाव:**
- धान और दलहन आधारित प्रणालियाँ अधिक कार्बन स्तर बनाए रखती हैं क्योंकि जल-प्रधान खेती से सूक्ष्मजीव गतिविधि बढ़ती है।
- गेहूँ और मोटे अनाज आधारित प्रणालियों में कार्बन स्तर कम पाया गया।

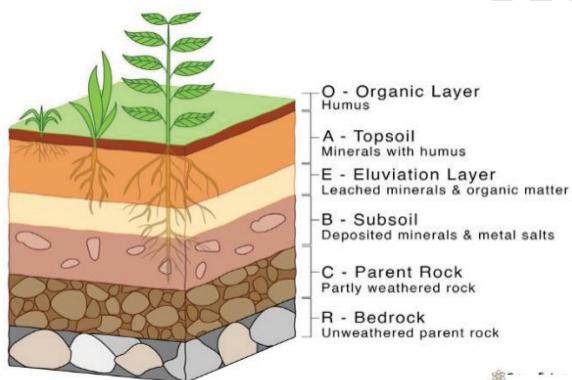
मृदा का स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है?

- कृषि का समर्थन:** भारत की 54% से अधिक कार्यबल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।
- स्वस्थ मृदा उच्च फसल उत्पादन और बेहतर पोषण गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।

Why Organic Carbon Matters?

- Retaining soil moisture
- Supporting microbial life
- Enhancing nutrient availability
- Sequestering carbon to mitigate climate change

- **खाद्य सुरक्षा:** कार्बनिक पदार्थ एवं पोषक तत्वों से समृद्ध मृदा अधिक लचीली और पौष्टिक फसलें उत्पन्न करती है।
- **पर्यावरणीय संतुलन:** स्वस्थ मृदा जल को नियंत्रित करती है, कार्बन को संग्रहित करती है, जैव विविधता को समर्थन देती है और बाढ़, सूखा तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध बफर का कार्य करती है।
- **आर्थिक प्रभाव:** खराब मृदा स्वास्थ्य से उत्पादकता घटती है, इनपुट लागत बढ़ती है और दीर्घकालिक भूमि क्षरण होता है — जिससे किसानों की आय और राष्ट्रीय GDP प्रभावित होती है।



संबंधित प्रयास और पहल

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना (2015):** इसका उद्देश्य प्रत्येक किसान को उनकी मृदा की पोषक स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करना है। यह संतुलित और विवेकपूर्ण उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देती है।
 - ▲ सरकार ने SHC योजना को समर्थन देने के लिए मृदा परीक्षण सुविधाओं को बेहतर किया है, जैसे मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम और डिजिटल ट्रैकिंग।

- **मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM):** यह राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देना है।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के साथ एकीकरण:** SHC और SHM योजनाओं को बेहतर समन्वय एवं प्रभाव के लिए RKVY के मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता घटक में मिला दिया गया है।

नीतिगत सिफारिशें

- **कार्बनिक कार्बन अवशोषण कार्यक्रम:** उन मृदाओं में अवशोषण को बढ़ावा देना जिनमें 0.25% से कम कार्बनिक कार्बन है, बेहतर फसल प्रणाली और सिंचाई समर्थन के माध्यम से।
- **कार्बन क्रेडिट प्रोत्साहन:** उन किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन देना जो सतत प्रथाओं के माध्यम से मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड को फँसाते और संग्रहित करते हैं।
- **जलवायु-लचीला फसल प्रबंधन:** जलवायु परिवर्तन शमन और मृदा पुनर्स्थापन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट फसल प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित करना।
- **राष्ट्रीय स्तर पर बनस्पति आवरण:** मृदा के खुलाव और कार्बन हानि को कम करने के लिए वृक्षारोपण एवं आवरण फसलों का विस्तार करना।

निष्कर्ष

- ICAR का अध्ययन संतुलित उर्वरक उपयोग, अनुकूलित फसल प्रणाली और जलवायु-संवेदनशील मृदा प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि भारत की मृदा में कार्बनिक कार्बन को पुनर्स्थापित और संरक्षित किया जा सके।
- यदि सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो कार्बनिक कार्बन की निरंतर गिरावट आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा, भूमि उत्पादकता और जलवायु स्थिरता को खतरे में डाल सकती है।

Source: TH

EEZ में मत्स्य पालन के सतत दोहन के नियम

समाचार में

- भारत सरकार ने नई गहरे समुद्री मत्स्य पालन नियमावली, 2025 अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य समृद्ध और समावेशी ब्लू इकॉनमी की परिकल्पना को साकार करना तथा भारत की 11,099 किमी लंबी तटरेखा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की विशाल क्षमता को उजागर करना है।

नियमों की मुख्य विशेषताएँ

- मछुआरों और सहकारी समितियों को सशक्त बनाना:** गहरे समुद्री मत्स्य पालन लाइसेंस के लिए उन्नत नौकाओं का उपयोग करने हेतु विशेष प्राथमिकता मछुआरा सहकारी समितियों और फिश फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FFPOs) को दी गई है।
- विदेशी नौकाओं पर प्रतिबंध:** भारत के EEZ में विदेशी मत्स्य नौकाओं का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ताकि संसाधन संप्रभुता और छोटे पैमाने के मछुआरों की रक्षा की जा सके।
- मदर-एंड-चाइल्ड नौका मॉडल:** भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के अंतर्गत मध्य-समुद्र में माल स्थानांतरण सक्षम करने हेतु यह मॉडल प्रस्तुत किया गया है।
 - इसमें बड़ी “मदर” नौकाएँ छोटी “चाइल्ड” नौकाओं को सहयोग देती हैं, जिससे तट पर भीड़ कम होती है, मत्स्य संचालन का विस्तार होता है और दक्षता बढ़ती है।
- हानिकारक मत्स्य प्रथाओं पर रोक:** LED लाइट फिशिंग, पेयर ट्रॉलिंग और बुल ट्रॉलिंग जैसी विधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके।
- मत्स्य प्रबंधन और कानूनी उपाय:** मछली प्रजातियों के लिए न्यूनतम कानूनी आकार निर्धारित किए जाएँगे और राज्य सरकारों व हितधारकों के परामर्श से फिशरीज

मैनेजमेंट प्लान तैयार किए जाएँगे ताकि सतत दोहन सुनिश्चित हो सके।

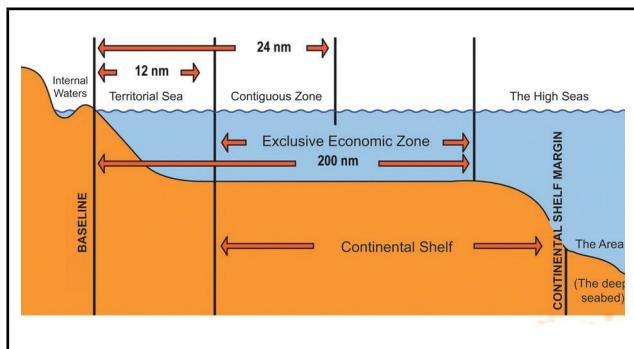
- डिजिटल पहुँच और निगरानी:** यंत्रीकृत और बड़ी मोटर चालित नौकाओं को ऑनलाइन रियलक्राफ्ट पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क एक्सेस पास लेना आवश्यक होगा।
 - यह पोर्टल मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल से एकीकृत है।

महत्व

- गहरे समुद्री मत्स्य पालन से राजस्व में वृद्धि और निकट-तटीय मत्स्य पालन पर निर्भरता में कमी।
- सहकारी शासन के माध्यम से तटीय समुदायों को सशक्त बनाना।
- संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना और अतिशोषण को रोकना।
- EEZ में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और समुद्री सुरक्षा को बेहतर करना।
- “भारतीय मूल(Indian origin)” लेबल के अंतर्गत भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना।

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone - EEZ) के बारे में

- कानूनी आधार:** 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्र के कानून पर अभिसमय (UNCLOS) के अंतर्गत स्थापित।
- सीमा:** किसी देश की तटरेखा के आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तारित।
- अधिकार:** किसी राष्ट्र को अपने EEZ में प्राकृतिक संसाधनों (जीवित और निर्जीव) की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन के लिए संप्रभु अधिकार प्राप्त होते हैं।
- महत्व:** EEZ समुद्री संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और रणनीतिक समुद्री हितों को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।



Source: TH

कृषि में डीप-टेक क्रांति को आकार देने वाली रिपोर्ट: WEF

संदर्भ

- विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) ने उद्योग और अकादमिक जगत के हितधारकों के सहयोग से एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट 'कृषि में डीप-टेक क्रांति को आकार देना' जारी की है।

परिचय

- रिपोर्ट ने सात डीप-टेक क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें कृषि परिवर्तन को आगे बढ़ाने की क्षमता है:
 - जनरेटिव एआई (Generative AI):** बड़े भाषा मॉडल और भविष्यवाणी विश्लेषण का उपयोग कीट, उत्पादन और श्रम अनुकूलन के लिए।
 - कंप्यूटर विज्ञन (Computer Vision):** वास्तविक समय की छवि/वीडियो डेटा का उपयोग फसलों की निगरानी, रोग/दोष पहचान एवं उत्पाद छंटाई के लिए।
 - एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT):** खेतों पर सेंसर/उपकरण जो स्थानीय स्तर पर डेटा संसाधित करते हैं, विशेषकर सिंचाई, उर्वरक और कीट नियंत्रण के लिए दूरस्थ/कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में।
 - उपग्रह-सक्षम रिमोट सेंसिंग (Satellite-enabled Remote Sensing):** पृथ्वी अवलोकन का उपयोग मृदा स्वास्थ्य, नमी, फसल स्थिति और आपूर्ति श्रृंखला जॉखिमों के लिए।

- रोबोटिक्स (ड्रोन/स्वायत्त प्रणालियाँ):** श्रम-गहन कार्य जैसे रोपाई, निराई, कटाई का स्वचालन; स्वार्म रोबोटिक्स आदि।
- CRISPR / जीन संपादन (Gene Editing):** जलवायु-लचीली, कीट/रोग-प्रतिरोधी फसल किस्मों का विकास पारंपरिक प्रजनन से तेजी से।
- नैनोप्रौद्योगिकी (Nanotechnology):** इनपुट्स (उर्वरक, कीटनाशक) का सटीक अनुप्रयोग, दक्षता में सुधार, अपशिष्ट और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी।
- चिंताएँ :** ग्रामीण से शहरी प्रवासन में वृद्धि, जलवायु चरम स्थितियों की तीव्रता, और प्राकृतिक संसाधनों (विशेषकर मृदा और जल) का तीव्रता से क्षरण सामूहिक रूप से उत्पादकता को खतरे में डाल रहे हैं और कृषि पर निर्भर आजीविकाओं को असुरक्षित बना रहे हैं।
- भारत से केस स्टडी :** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा CRISPR तकनीक से विकसित धान की एक किस्म, जो सूखा/लवणता सहनशील है, अधिक उत्पादन देती है और उत्सर्जन कम करती है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में रिमोट सेंसिंग + ड्रोन + मोबाइल ऐप्स का उपयोग, जिससे हानि का आकलन तीव्र और पारदर्शी हुआ।

कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल

- यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच की कृषि पहल के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI4AI) द्वारा जारी की गई है।
- 2021 में स्थापित, AI4AI विभिन्न क्षेत्रों में हितधारकों को उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में सहायता कर रहा है ताकि कृषि अधिक समावेशी, सतत और कुशल बन सके।

भारत सरकार की पहलें

- भारत में कृषि का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (IDEA):** यह एक ढाँचा है जो किसानों के संघीय डेटाबेस की संरचना तैयार करता है, जिससे उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए नवोन्मेषी समाधान संभव हो सकें।

- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A):** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आधुनिक तकनीकों जैसे AI, ML, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन आधारित परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया जाता है।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM):** एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जो APMC मंडियों को जोड़ता है, जिससे कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनता है और किसानों, व्यापारियों व मंडियों को डिजिटल सेवाएँ मिलती हैं।
- ICAR द्वारा मोबाइल ऐप्स:** ICAR, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विकसित 100 से अधिक मोबाइल ऐप्स किसानों को फसल, बागवानी, पशु चिकित्सा, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर उपयोगी जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
- मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना :** इसका उद्देश्य मृदा की पोषक स्थिति का आकलन करना और किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन के लिए अनुकूलित सिफारिशें प्रदान करना है।
- ‘किसान ई-मित्र’:** एक वॉयस-आधारित एआई चैटबॉट, जो किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता करता है।
- राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली :** जलवायु परिवर्तन के कारण फसल हानि से निपटने के लिए AI और ML का उपयोग कर कीट संक्रमण का पता लगाती है तथा समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करती है।
- नमो ड्रोन दीदी (Namo Drone Didi):** यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है (2023-24 से 2025-26 तक) जिसका उद्देश्य कृषि में उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना है ताकि दक्षता बढ़े, फसल उत्पादन सुधरे और संचालन लागत कम हो।
- सटीक कृषि को प्रोत्साहन:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसी पहलें ड्रिप सिंचाई और

फर्टिंगेशन जैसी तकनीकों को बढ़ावा देती हैं, जिससे उर्वरकों (जैसे यूरिया) का अधिक कुशल उपयोग होता है तथा पोषक तत्व सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचते हैं।

निष्कर्ष

- वैश्विक कृषि एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है: चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों (मृदा, जल) का क्षरण, वृद्ध और घटती किसान जनसंख्या, तथा बढ़ती खाद्य मांग शामिल हैं।
- पारंपरिक तरीकों से अकेले बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना और स्थिरता बनाए रखना संभव नहीं होगा।
- रिपोर्ट का तर्क है कि कृषि में डीप-टेक का उपयोग भविष्य की कृषि प्रणालियों को सुरक्षित बना सकता है: उत्पादकता बढ़ा सकता है, लचीलापन विकसित कर सकता है और स्थिरता में सुधार कर सकता है।

Source: BL

संक्षिप्त समाचार

चित्तरंजन दास

समाचार में

- लोकसभा ने स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।

चित्तरंजन दास (1870 – 1925) के बारे में

- परिचय :** वे लोकप्रिय रूप से “देशबंधु (राष्ट्र के मित्र)” के नाम से जाने जाते थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, वकील, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सुधारक थे।
 - उन्होंने 1908 में अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष का बचाव किया और बाद में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए।
- मुख्य योगदान (Key Contributions):**
 - वे महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन (1919–22) के प्रतिभागी थे।

- ▲ 1923 में उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, ताकि विधान परिषदों में प्रवेश कर अंदर से औपनिवेशिक शासन का विरोध किया जा सके।
- ▲ 1924 में वे कलकत्ता के पहले निर्वाचित मेयर बने और शहरी सुधारों तथा नगरपालिका प्रशासन में भारतीय सशक्तिकरण के लिए कार्य किया।
- ▲ उन्होंने कविताएँ, निबंध और पुस्तकें लिखीं, जिनमें 'इंडिया फॉर इंडियन्स' और 'फ्रीडम थ्रो डिसओबिडेंस' शामिल हैं।

Source: AIR

वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव

संदर्भ

- भूटान की रॉयल सरकार द्वारा ग्लोबल पीस प्रेरण फेस्टिवल (GPPF) का उद्घाटन थिम्फू में किया गया।

परिचय (About)

- यह 16-दिवसीय उत्सव एक वैश्विक पहल है, जो विश्व शांति और चल रहे वैश्विक संघर्षों के बीच मानवता के उपचार हेतु प्रार्थनाओं को समर्पित है।
- यह प्रथम ग्लोबल पीस प्रेरण फेस्टिवल (GPPF) था, जिसमें बौद्ध धर्म की तीन प्रमुख शाखाओं — महायान, थेरवाद और वज्रयान — के धार्मिक नेताओं और विद्वानों ने भाग लिया।
- उत्सव की प्रमुख घटनाओं में से एक जाब्जी है, जो एक गहन वज्रयान बौद्ध अनुष्ठान है। इसे नकारात्मक कर्म को शुद्ध करने और विनाशकारी शक्तियों को दूर करने वाला माना जाता है।
- एक आध्यात्मिक संकेत के रूप में, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष, जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में विराजमान हैं, भारत की ओर से गुडविल गिफ्ट के रूप में थिम्फू पहुँचे।
- ग्लोबल पीस प्रेरण फेस्टिवल पृथ्वी पर शांति के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में खड़ा है, जो भूटान

की अद्वितीय आध्यात्मिक विरासत का उत्सव मनाता है और उन साझा बौद्ध मूल्यों की पुनः पुष्टि करता है जिन्होंने लंबे समय से भारत-भूटान संबंधों का मार्गदर्शन किया है।

Source: TH

अंगोला

समाचार में

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अंगोला की राजकीय यात्रा पर हैं। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्र अंगोला की प्रथम यात्रा है, जिसका उद्देश्य भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन (IAFS) के ढाँचे के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना है।

अंगोला के बारे में (राजधानी: लुआंडा)

- **अवस्थिति:** अंगोला दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके दक्षिण में नामीबिया, पूर्व में ज़ाम्बिया, उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पश्चिम में अटलांटिक महासागर हैं।
- **राजनीतिक परिचय:** अंगोला ने 1975 में पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह स्वतंत्रता MPLA (पीपल्स मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला) के नेतृत्व में वर्षों के औपनिवेशिक विरोध संघर्ष के बाद मिली।
- **आर्थिक प्रोफाइल :** अंगोला, नाइजीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। हीरे इसका एक अन्य प्रमुख निर्यात क्षेत्र हैं।
- **भौगोलिक प्रोफाइल :** अंगोला लगभग चौकोर आकार का है, जो संकीर्ण तटीय मैदान से उठकर 1,000–2,000 मीटर ऊँचाई वाले केंद्रीय पठार तक फैला है।
 - ▲ इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट मोक्को (Mount Moco) है, जो हुआम्बो के पास स्थित है। प्रमुख नदियाँ कुआंजा, कुनने और कुआंगो हैं।

भारत-अंगोला संबंध

- दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1985 में स्थापित हुए और भारत का दूतावास 1986 में लुआंडा में खोला गया।

- द्विपक्षीय व्यापार मूल्य \$4 बिलियन से अधिक है, जिसमें प्रमुख हिस्सा अंगोला से कच्चे तेल का आयात है। भारत से औषधियाँ, वाहन, मशीनरी और वस्त्रों का निर्यात होता है।
- अंगोला को भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट, ITEC कार्यक्रम और पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क (दूरस्थ शिक्षा और टेलीमेडिसिन) से लाभ मिलता है।
- सहयोग रक्षा प्रशिक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि-उद्योगों तक विस्तारित है।

Source: TH

असम बहुविवाह निषेध विधेयक-2025

संदर्भ

- असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि असम बहुविवाह निषेध विधेयक-2025 विधानसभा में पेश किया जाएगा।

परिचय

- इसमें प्रस्ताव है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी के जीवित रहते हुए कई बार विवाह करता है, तो यह दंडनीय अपराध होगा, जिसके लिए सात वर्ष तक की कैद का प्रावधान है।
- इस अपराध को संज्ञेय अपराध बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त को तुरंत जमानत नहीं मिलेगी।
- यह कानून राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों और संविधान की षष्ठि अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जनजातीय जिलों पर लागू नहीं होगा।
- विशेष कोष :** विधेयक में राज्य सरकार द्वारा एक विशेष कोष स्थापित करने का प्रावधान भी है, जिसके माध्यम से उन महिलाओं को मुआवजा दिया जाएगा जो “बहुविवाह की शिकार” हैं।
- यह विधेयक असम की सामाजिक संरचना और लैंगिक न्याय को पुनः आकार देने के व्यापक अभियान का भाग है।

Source: IE

भारत विकास और रणनीतिक कोष (IDSF)

संदर्भ

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने दीर्घकालिक विकास और वैश्विक आर्थिक सुरक्षा को समर्थन देने के लिए इंडिया डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजिक फंड (IDSF) स्थापित करने का सुझाव दिया है।

इंडिया डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजिक फंड (IDSF)

- उद्देश्य (Aim):** एक “ट्रिविन-आर्म” राष्ट्रीय कोष का निर्माण करना, जो घरेलू और वैश्विक बचत को जुटाए और परिपक्व परिसंपत्तियों से पूँजी को पुनर्चक्रित कर नई उत्पादक क्षमता में लगाए।
- यह वार्षिक बजट से परे दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास के लिए एक स्थायी वित्तीय इंजन का निर्माण करेगा।
- CII ने सुझाव दिया है कि IDSF के दो अंग होंगे:

1. डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आर्म :

- केन्द्र:** दीर्घकालिक घरेलू प्राथमिकताओं पर।
- क्षेत्र:** अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक कॉरिडोर, MSME विस्तार, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, शहरी अवसंरचना।
- भूमिका:** एंकर निवेशक के रूप में कार्य करेगा, जिससे पेंशन फंड, संप्रभु निधि और संस्थागत निवेशक (घरेलू और विदेशी दोनों) आकर्षित होंगे।

2. स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट आर्म :

- केन्द्र:** भारत की आर्थिक और सुरक्षा हितों के लिए महत्वपूर्ण विदेशी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना।
- लक्ष्य:** ऊर्जा परिसंपत्तियाँ, महत्वपूर्ण खनिज, अग्रणी प्रौद्योगिकियाँ (AI, सेमीकंडक्टर)।

भारतीय उद्योग परिसंघ

- प्रकार :** गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-नेतृत्व और उद्योग-प्रबंधित संगठन।
- स्थापना :** 1895 (इंजीनियरिंग और आयरन ट्रेड्स एसोसिएशन के रूप में; 1992 में नाम बदलकर CII किया गया)।

- **मुख्यालय :** नई दिल्ली।
- **सदस्यता :** 9,000 से अधिक प्रत्यक्ष सदस्य (निजी एवं सार्वजनिक उद्यम, SMEs, MNCs) और 3,00,000 अप्रत्यक्ष सदस्य (क्षेत्रीय संघों के माध्यम से)।
- **कवरेज :** भारत में 62 कार्यालयों और विदेशों में 8 कार्यालयों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को शामिल करता है।
- CII सरकारों और विचार नेताओं के साथ मिलकर कार्य करता है और उद्योग के लिए दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता एवं व्यापारिक अवसरों को बढ़ाता है।

Source: BS

बॉक्सफिश

समाचार में

- कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने एक गणितीय मॉडल विकसित किया है जो ऑर्नेट बॉक्सफिश की त्वचा के पैटर्न को पुनः निर्मित करता है।
- उनका कार्य एलन ट्र्यूरिंग के 1952 के पैटर्न निर्माण सिद्धांत पर आधारित है, जो बताता है कि प्रसार और रासायनिक प्रतिक्रियाएँ ग्राकृतिक डिजाइन जैसे तेंदुए

के धब्बे एवं सीपियों की लहरदार आकृतियाँ — जिन्हें ट्र्यूरिंग पैटर्न कहा जाता है — बना सकती हैं।

बॉक्सफिश के बारे में

- ये छोटे, छिछले जल में पाए जाने वाले समुद्री मछलियाँ हैं, जो ओस्ट्रासिओनिट्डे (*Ostraciontidae*) परिवार से संबंधित हैं।
- इनकी कठोर, डिब्बेनुमा कवच (carapace) जुड़ी हुई प्लेटों से बना होता है, जो इनके शरीर के अधिकांश हिस्से को ढकता है, केवल आँखें, मुँह, पंख और पूँछ को छोड़कर।
- ये विश्वभर के गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती हैं।
- ये चमकीले रंगों वाली होती हैं और कभी-कभी इनके सिर पर सींग जैसी आकृतियों के कारण इन्हें काउफिश भी कहा जाता है।
- यद्यपि ये खाने योग्य होती हैं और अक्सर सजावटी वस्तुओं के रूप में सुखाई जाती हैं, लेकिन छूने पर बॉक्सफिश एक विषेला पदार्थ छोड़ती हैं जो आसपास की मछलियों को हानि पहुँचा सकता है।

Source : IE

